भारतीय जनता पार्टी

(केन्द्रीय कार्यालय)
11, अशोक रोड नई दिल्ली – 110001
फोन नं. : 23005700; **फैक्स :** 23005787

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद श्री प्रकाश जावडेकर द्वारा गुरूवार, 25 सितम्बर, 2008 को जारी प्रेस वक्तव्य

1. इंडियन मुजाहिदीन से संबंध रखने वाले 5 पाकिस्तान–प्रशिक्षित आतंकवादियों की गिरफ्तारी के पश्चात् मुंबई पुलिस ने जो हाल में खुलासे किए है उन पर केन्द्र सरकार को अपनी प्रतिक्रिया तत्काल देनी चाहिए। इन आतंकवादियों से गोला–बारूद, हथियारों और विस्फोटकों की जो भारी मात्रा में बरामदगी हुई है उससे इनके द्वारा अगला आतंकवादी हमला करने की तैयारी का स्पष्ट संकेत मिलता है। विभिन्न राज्यों की पुलिस, सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों से यह बात पुख्ता रूप में साबित हो गई है कि 2005 से लेकर अब तक बंगलौर, हैदराबाद, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर और दिल्ली जैसे शहरों में किए गए धमाकों में इंडियन मुजाहिदीन का सीधा हाथ था। मजे की बात यह है कि इंडियन मुजाहिदीन ने इनमें से कई हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार की है। इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों द्वारा हर बार भेजे गए ई–मेल में ऐसी आतंकवादी करतूतों के लिए एक ही तरह के तर्क दोहराए गए थे। ई–मेल संदेश भेजने के पीछे इनका इरादा साम्प्रदायिक उन्माद फैलाना था।

अब पुलिस के पास यह साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत हैं कि इंडियन मुजाहिदीन का आईएसआई, हूजी तथा लश्करे–तैयबा जैसे अन्य आतंकी संगठनों के साथ संबंध है। सिमी तथा इंडियन मुजाहिदीन दोनों ही का प्रणेता अकेला और वही आतंकवादी सफदर नागौरी है। अब तक जो साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि इंडियन मुजाहिदीन और सिमी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

यह देखकर कुतूहल होता है कि कांग्रेस–नीत संप्रग सरकार बात तो 'सख्त' कर रही है किंतु कार्रवाई 'नरम' कर रही है। इंडियन मुजाहिदीन के विरूद्ध सख्ती बरतने में सरकार के निकम्मेपन पर भारतीय जनता पार्टी हैरान–परेशान है। यह समझ से परे है कि सिमी पर तो रोक लगा दी गई है पर इंडियन मुजाहिदीन को खुला छोड़ दिया गया है। ***भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इंडियन मुजाहिदीन पर विधि–विरूद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 के अधीन तुरंत रोक लगाई जाए।***

2. कांग्रेस पार्टी की यह सोची–समझी रणनीति है कि आतंकवाद के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के बारे में उसके अलग–अलग नेताओं द्वारा, अलग–अलग मौकों पर, अलग–अलग बयान देकर राष्ट्र को भ्रमित कर दिया जाए। श्री राहुल गांधी का बयान भी 'भ्रम फैलाने वाली' उसी रणनीति का हिस्सा है। जहां राहुल आतंकवाद के विरूद्ध नए सख्त कानून की बात कर रहे हैं, वहीं मनमोहन सिंह सरकार के एक के बाद एक मंत्री जोर देकर कह रहे हैं कि उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। मोइली समिति ने कुछ और तरह की सिफारिशें की हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेसी नेतागण आतंकवाद पर सख्ती बरतने की बात कहकर जनता के क्रोध को शांत करने के लिए जबानी जमा–खर्च कर रहे हैं, किंतु अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए वे असलियत में आतंकवाद के विरूद्ध नरमी बरत रहे हैं। उनकी रणनीति है कि इस मुद्दे पर भ्रम जारी रखा जाए और इसको और अधिक बढ़ा दिया जाए।

श्री राहुल गांधी को भाजपा स्मरण कराना चाहती है कि पोटा विफल कानून नहीं है, बल्कि पोटा के अधीन सिद्धदोष अफज़ल को फांसी न दिया जाना विफल सरकार का उदाहरण है। ***जो कुछ विफल हुआ है वह पोटा नहीं है, बल्कि संप्रग है***।

भाजपा राहुल गांधी से दो प्रश्न पूछना चाहती है।

- **पोटा में क्या–क्या कमियां है, कारण सहित बताएं ?**
- **नए कानून में वे क्या उपबंध होंगे, जो सख्त भी होंगे किन्तु पोटा से भिन्न होंगे ?**

भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आतंकवाद पर व्यापक बहस करने की चुनौती देती है। भाजपा ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि वह सख्त कानून चाहती है – आतंकवाद को कुचलने के लिए व्यापक रणनीति चाहती है। कानून का नाम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कांग्रेस को पोटा नाम पसंद नहीं है तो वह इसको सोटा या राहुल एक्ट का नाम दे सकती है। किन्तु सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए और आतंकवाद को कुचल देना चाहिए।

कांग्रेस का यह तर्क न केवल बकवास है, बल्कि आतंकवाद को उचित भी ठहराता है कि दंगों और रथ यात्रा से आतंकवाद को बढ़ावा मिला है। फिर, कांग्रेस वैश्विक आतंकवाद के बारे में किस प्रकार सफाई दे सकती है।

3. समाजवाद पार्टी के नेता श्री अमर सिंह के द्वारा लगाए गए इलज़ाम "उल्टा चोर कोतवाल को डांटे" की जीती–जागती मिसाल हैं। यह रिश्वत देने वाले द्वारा रचा गया मंच–अभिनीत दृश्य (Stage-managed show) था। यह गवाहों को प्रभावित करने तथा धमकाने का प्रयास है। यह चल रही संसदीय जांच में सीधा हस्तक्षेप है। यह संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन है।

यह जांच का विषय है कि जिस गवाह को आज बयान देना था वह आज अमर सिंह के घर पर मौजूद है। तथ्य स्वयं बोलते हैं। भाजपा को आशा है कि संसदीय समिति विशेषाधिकार के इस उल्लंघन पर उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

(श्याम जाजू)
मुख्यालय प्रभारी